



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226709  
CG-DL-E-22042021-226709

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943

No. 225]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/CHAITRA 30, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

**सा.का.नि. 282(अ).**—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ज) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम दिनांक 25 सितंबर, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. “राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019” में नियम 4 में, उप-नियम (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा:-

**“स्पष्टीकरण:** इस उप-नियम के उद्देश्य हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अध्यक्ष अथवा कोई पूर्णकालिक सदस्य केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है तो स्वायत्त बोर्डों में उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा।”

[सं. वी. 11012/13/2019-एमईपी (पार्ट)]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 सा.का.नि.647(अ) दिनांक 12 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021.

**G.S.R. 282(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (j) and (k) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019, namely:—

1. (1) These Rules may be called the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force from 25th September, 2020.

2. In the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019, in rule 4, in sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:—

*“Explanation:—* For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where the President or a whole-time Member is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in Autonomous Boards shall be treated as deputation.”

[No. V.11012/13/2019-MEP(Pt.)]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.

**Note:** National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R.647(E), dated the 12th September, 2019.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

**सा.का.नि. 283(अ).**—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:- अर्थात:

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें और आस्तियों, व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) संशोधन नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 25 सितंबर, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 में:

(क) नियम 5 में, उप-नियम 5(2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

**“स्पष्टीकरण:** इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है की जहां अध्यक्ष, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की सेवा में है तो आयोग में उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा।”

(ख) नियम (13) में, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात:

(1क) यदि आयोग का सचिव, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की सेवा में है तो उनके वेतन और भत्तों को उन पर लागू नियमों या उप-नियम (1) के अनुसार, जो भी अधिक हो, विनियमित किया जाएगा।

**“स्पष्टीकरण:** इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है की जहां सचिव, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की सेवा में है तो आयोग में उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा।”

[सं. वी. 11012/13/2019-एमईपी]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

**नोट:** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें तथा आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजना की घोषणा) नियम, 2019 दिनांक 12 सितंबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (1) में सा.का. नि. 650 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2021.

**G.S.R. 283(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d) (e), (f), (g), (h) and (q) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force from 25th September, 2020.

2. In the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019:-

(a) In rule 5, in sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation:- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the Chairperson is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in the Commission shall be treated as deputation.”;

(b) In rule 13, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

“(1A) If the Secretary to the Commission is in service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

*Explanation:-* For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where the Secretary is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in the Commission shall be treated as deputation.”

[No. V.11012/13/2019-MEP]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.

**Note:** National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R.650(E), dated the 12th September, 2019.